आधुनिक करघों पर सब्सिडी

*222. **श्री उदय प्रताप सिंह:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आधुनिक करघों पर सब्सिडी बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और सब्सिडी की प्रस्तावित राशि क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) हाल ही में सरकार ने लघु विद्युतकरघा एककों को आधुनिक बुनाई मशीनों की 60 लाख रुपये की लागत में 20% का प्रोत्साहन दे कर और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त सभी सहकारी बैंकों और अन्य वास्तविक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन०बी०एफ०सी०) सहित बड़े नेटवर्क से उसकी अधिप्राप्ति के लिए ऋण प्राप्त करने की सुविधा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करके प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।

Increasing subsidy in modern looms

†*222. SHRI UDAY PRATAP SINGH: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether the Government are considering to increase subsidy on modern looms;

(b) if so, the details thereof and the proposed amount of subsidy?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI SYED SHAHNAWAZ HUSSAIN): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes Sir.

(b) Recently Government has modified the guidelines of the Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) by offering the small scale powerloom

†Original notice of the question was received in Hindi.

units an additional option of an incentive of 20% of the cost of modern weaving machinery upto Rs. 60 lakhs and the facility to obtain credit for its acquisition from a larger network, including all cooperative banks and other genuine Non-Banking Financial Companies (NBFC) recognized by the Reserve Bank of India.

श्री उदय प्रताप सिंह: माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनकी सूचना के अनुसार 60 लाख तक की लागत पर बीस प्रतिशत का प्रोत्साहन सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा, यह अच्छी बात है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की गरीबी और बेरोजगारी एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। अत: आधुनिक करघों, जो बिजली से चलते हैं, के साथ-साथ पारंपरिक हथकरघों को भी प्रोत्साहन देना आवश्यक है, क्योंकि वे रोजगार की ज्यादा संभावनाएं कम लागत में उपलब्ध करा देते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार कई राज्यों में ऐसे गांव हैं जहां अभी तक विद्युतिकरण भी नहीं हुआ। वहां हथकरघा ही गरीबी और बेरोजगारी का एकमात्र उत्तर है। इसलिए इस दिशा में क्या कोई योजना सरकार ने बनाई है या बना रही है?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने कहा कि एक अच्छी योजना हमारी सरकार ने पॉवरलूम के लिए शुरू की है, कि 60 लाख की कीमत तक जो लोग पॉवरलूम में मशीनरी लेंगे उनको बीस परसेंट सब्सिडी दी जाएगी। इस तरह की कई योजनाएं हथकरघा में भी चल रही हैं। उसके लिए एक अलग से विभाग है जो उस काम को देखता है और उसके लिए कई योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई हैं।

श्रीमती सविता शारदा: सभापति महोदय, अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि मशीनरी अपग्रेडेशन के लिए 20 परसेंट की धनराशि निश्चित की है, मैं उन से जानना चाहती हूं कि क्या टैक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से इस अपग्रेडेशन को बढ़ाने के लिए उन के पास कोई सुझाव आया है? अगर आया है तो उन्होंने उस में कितनी बढ़ोतरी की है और अभी तक उन्होंने इस मद में कितनी धनराशि अपग्रेडेशन के लिए आवंटित की है? सभापति महोदय, हमारे यहां सूरत टैक्सटाइल का गढ़ है तो उस के लिए उन्होंने कितनी धनराशि आवंटित की है?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति जी, श्री एन॰के॰ सिंह कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर और प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हम ने यह एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जिस के अंतर्गत पावरलूम के लिए हम बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं, लेकिन इस प्रश्न में पावरलूम को सब्सिडी देने की बात थी तो पिछले महीने ही कैबिनेट ने इसे पास किया है और अब हम इसे शुरू करने जा रहे हैं। सभापति जी, अब चूंकि सूरत में सब से ज्यादा लूम्स हैं तो उस को इस का लाभ होगा।

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन्, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अपने देश में आधुनिक बुनाई मशीनों की संख्या कितनी है और यह योजना जो अभी आप ने शुरू

भी नहीं की है, उस के बारे में आप का आंकलन क्या है कि इस पर कितना खर्चा करना पड़ेगा? साथ ही इस से कितने एककों को आप फायदा पहुंचा पाएंगे और यह फायदा किस हद तक पहुंचेगा?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति जी, अपने देश में पावरलूम की संख्या करीब 16 लाख है। उन में जो कपड़ा बनता है उस में 60 से 62 प्रतिशत कपड़ा पावरलूम के जरिए बनता है। इसलिए यह योजना पावरलूम के लिए बहुत बड़ी मदद के रूप में है। पहले भी हम ने इस के लिए बहुत सारी योजनाएं चलायी हैं, लेकिन खासकर पावरलूम अपग्रेडेशन बहुत दिनों से नहीं हुआ था। इसे ध्यान में रखकर सरकार ने निर्णय लिया है और यह टैक्नॉलाजिकल अपग्रेडेशन फंड (टी॰यू॰एफ॰) स्कीम बनाई जिस के तहत जो लोग नए लूम लगाएंगे, उस के अपग्रेडेशन के लिए हम ने यह सब्सिडी दी है। इस के तहत अगर वे 60 लाख की लागत लगाएंगे तो उन को 20 परसेंट की सब्सिडी सरकार देगी। सभापति जी, इस से पावरलूम के क्षेत्र में बहुत बड़ा उद्धार होने वाला है।

BPL families identified under SJGSY

*223. SHRI MURLI DEORA: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of BPL families identified under the Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana, State-wise;

(b) the names of States which did not contribute their share of funds along with the reasons therefor;

(c) whether there were large scale diversions and mis-utilization of the funds and if so, the number of complaints received in this regard, State-wise; and

(d) the steps taken to check the deficiencies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI ANNASAHEB M.K. PATIL) (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No specific survey has been conducted for identification of Below Poverty Line (BPL) families under the Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY). However, during each Five Year Plan, the Ministry of Rural Development assists the State Government to conduct a BPL